>

Title: Need to enhance the allocation of funds earmarked for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for hilly & forest areas of Uttrakhand keeping in view the adverse geographical conditions prevailing in the region.

**श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):** मैं माननीय सदस्यों का ध्यान केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों की स्वीकृति की भांति, उत्तराखंड राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों हेतु योजना की कुल लागत का दस प्रतिशत किसी संभावित विचलन के लिए, केन्द्रीय सड़क निधि की भांति स्वीकृति जारी करने हेतु धनराशि प्राविधानित की जाती है। मैदानी राज्यों में तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है। इसलिए वहां विकास भी शीघ्रता से होता है, परन्तु पहाड़ी राज्यों में वन क्षेत्र अधिक होने के कारण वहां सड़क निर्माण के लिए पहले वन विभाग से स्वीकृति लेनी होती है तथा स्वीकृत योजना की लागत राशि की 47 प्रतिशत राशि वन विभाग के मद " कैम्पा " में पर्वतीय राज्यों द्वारा देनी पड़ रही है तथा अनुरक्षण मद में भी राज्य सरकार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों का वित्तीय भार सहन करना पड़ता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने के लिए कोई नीति बनाई जाये क्योंकि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लगभग 85 प्रतिशत क्षेत्र वन भूमि आच्छादित हैं। साथ ही मैदानी राज्यों की प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु स्वीकृत पूरी धनराशि का उपयोग उसी राज्य में हो जाता है जबकि वन क्षेत्र होने के कारण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति हेतु पर्वतीय राज्य को कुल आबंटित धनराशि का 47 प्रतिशत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को चला जाता है और बाकी बचा 53 प्रतिशत ही स्वीकृत योजना मार्ग निर्माण पर व्यय हो पाता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्वतों पर मार्ग निर्माण में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक व्यय आता है। इस पर भी 47 प्रतिशत "" कैम्पा " में देने के पश्चात सिर्फ 53 प्रतिशत ही निर्माण पर खर्च होता है जो काफी कम है, जिससे वहां का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह इस पर विचार कर आवश्यक संशोधन करें, जिससे मार्ग निर्माण के विकास पर खर्च होने वाली पूरी राशि का पूर्ण उपयोग हो सके तथा पर्वतीय क्षेत्र भी मैदानी क्षेत्रों की तरह विकास कर सकें।